

आईआईटी की जमीन का रास्ता साफ

सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को वन मंत्रालय से मिला आश्वासन

इंदौर (नप्र)। आईआईटी की जमीन पर संकट दूर होता नजर आ रहा है। सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने दावा किया कि केंद्र ने 80 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन को मुक्त करने की सहमति दे दी है।

सांसद श्री गुड्डू व गजेंद्रसिंह राजूखेड़ी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश से मुलाकात की। श्री गुड्डू के अनुसार वनमंत्री का ध्यान इंदौर व आईआईटी की जरूरतों की ओर आकृष्ट किया। उन्हें बताया गया कि अभी जिस भवन में आईआईटी

संचालित हो रहा है वहाँ समस्याएँ हैं। शहर व विद्यार्थियों के हित में इंस्टीट्यूट का नया भवन जल्द से जल्द बनना जरूरी है। श्री रमेश ने आश्वासन दिया है कि 80 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन का भू-उपयोग बदलने की अनुमति जारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों केंद्रीय वन मंत्रालय ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। इसमें 80 हेक्टेयर वनभूमि के भूउपयोग बदलने की अनुमति माँगी गई थी। जमीन का यह हिस्सा आईआईटी को आवंटित 500 एकड़ जमीन में शामिल है।

महू में होगी चिह्नित

श्री गुड्डू के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आईआईटी के कारण सिमरोल में उजड़ने वाले वन क्षेत्र की पूर्ति महू में की जाएगी। महू में रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन को चिह्नित किया जाएगा। सिमरोल में आईआईटी बनने से जो सात हजार से ज्यादा पेड़ कटेंगे, उनकी जगह महू की जमीन पर 40 हजार पौधे रोपे जाएँगे। इस बारे में जल्द ही आदेश जारी होने की उम्मीद की जा रही है।